



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2000/पौष 29, 1921

No. 10]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2000/PAUSA 29, 1921

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2000

सं. एम/13011/3/99-प्रशा. IV.—भारत सरकार ने मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली को समुचित ढंग से सुदृढ़ करने हेतु उपर्योगों की अनुशंसा करने की दृष्टि से प्रणाली की कमियों को आलोचनात्मक जांच करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग में डा. सी. रंगाराजन, राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में होंगे और निम्नलिखित अधिकारी अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे :—

भारत सरकार ने मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली को समुचित ढंग से सुदृढ़ करने हेतु उपर्योगों की अनुशंसा करने की दृष्टि से प्रणाली की कमियों को आलोचनात्मक जांच करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग में डा. सी. रंगाराजन, राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में होंगे और निम्नलिखित अधिकारी अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे :—

- (1) श्री वी.आर.राव, भूतपूर्व-निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार।
- (2) श्री एस.एम.विधवांस, भूतपूर्व-निदेशक (अर्थ एवं सांख्यिकी) महाराष्ट्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ।
- (3) प्रो. जे.राय, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान।
- (4) डा. प्रेम नारायण, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक, आई.ए.आर.आई. और भूतपूर्व निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान।
- (5) डा. राकेश मोहन, महानिदेशक, एनसीईआर।
- (6) डा. वी.आर.पंचमुखी, महानिदेशक, गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली।
- (7) डा.वाई.वेणुगोपाल रेड्डी, उप राज्यपाल, भारतीय रिजर्व बैंक।
- (8) डा. के. श्रीनिवासन, कार्यकारी निदेशक, भारत का जनसंख्या प्रतिष्ठान और भूतपूर्व निदेशक, जनसंख्या अध्ययन का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान।

(9) प्रा. एस. तेन्दुलकर, दिल्ली स्कूल आफ इकॉनोमिक्स और उपाध्यक्ष सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय सत्राहकार बोर्ड।

(10) डा. ए.बी.एल.श्रीवास्तव, मुख्य परामर्शदाता, शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि. और भूतपूर्व प्रोफेसर, एनसीईआरटी।

(11) डा. फ्रेडी आरडेशिर मेहता, प्रख्यात निजी सेवा अर्थ शास्त्री और निदेशक, मैसर्स टाटा सन्स लि।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सेवा-शर्तें इस प्रकार हैं :

(I) मौजूदा सांख्यिकी प्रणाली की कमियों की समयबद्धता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता के संदर्भ में आलोचनात्मक जांच करना।

(II) प्रशासनिक ढांचे के भिन्न-भिन्न स्तरों पर सरकार में नीति और आयोजना के प्रयोजनार्थ समयबद्ध और विश्वसनीय सांख्यिकी के सृजन हेतु सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों को दूर करके इसे सुदृढ़ करने के उपायों की अनुशंसा करना।

(III) देश में विकन्द्रीकृत सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास को सुनिश्चित करने हेतु स्थाई और कारगर समन्वयक मकानिज्म की अनुशंसा करना।

(IV) सांख्यिकीय सूचना के संग्रहण के लिए मौजूदा विधायन की समीक्षा करना और समयबद्ध विश्वसनीय और पर्याप्त सांख्यिकी के संगृहण और प्रसार के प्रयोजन को प्राप्त करने हेतु, जहां आवश्यक हो, संशोधन की अनुशंसा करना।

(V) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सांख्यिकी पक्ष) और भारत की अन्य सांख्यिकीय इकाईयों मौजूदा संगठन की समीक्षा करना और सांख्यिकी सेवाओं को वृद्धि और विकास से निपटने हेतु कर्मचारीवृन्द और प्रशिक्षण अपेक्षाओं की अनुशंसा करना।

(VI) भारत सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की रेज की सांख्यिकीय लेखा-परीक्षा शुरू करने की आवश्यकता की जांच करना और इसके बारे में उपयुक्त अनुशंसा करना, और

(VII) देश में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने के लिए अन्य उपायों की अनुशंसा करना।

3. आयोग की सहायता के लिए अपर सचिव के स्तर पर पूर्णकालिक सचिव की अध्यक्षता वाला सचिवालय होगा। समुचित बोर्डिंग/लोजिंग, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और परिवहन व्यवस्था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसे समय-समय पर जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसे आबंटित बजट में से सभी कार्यकलापों में हुए व्यय को पूरा करेगा।

4. आयोग द्वारा इसकी स्थापना की तारीख से बारह महीनों की अवधि में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्मावना है।

एन.एस. शास्त्री, महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रा. प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 19th January, 2000

No. M/13011/3/99-Admn. IV.—The Government of India has decided to establish a National Statistical Commission to critically examine the deficiencies of the present statistical system with a view to recommending measures for a systematic revamping of the system. The Commission will consist of Dr. C. Rangarajan, Governor, Andhra Pradesh, as its part-time Chairman and the following as part-time members :

- (1) Shri V. R. Rao, ex-Director, Central Statistical Organisation and UN Advisor
- (2) Shri S. M. Vidhwans, ex-Director (Economics & Statistics), Government of Maharashtra and UN expert
- (3) Prof. J. Roy, Professor Emeritus at Indian Statistical Institute
- (4) Dr. Prem Narain, Emeritus Scientist, IARI and ex-Director, Indian Agricultural Statistics Research Institute
- (5) Dr. Rakesh Mohan, Director-General, NCAER
- (6) Dr. V. R. Panchmukhi, Director-General, Research and Information System for the Non-Aligned and other Developing Countries
- (7) Dr. Y. Venugopal Reddy, Deputy Governor, Reserve Bank of India
- (8) Dr. K. Srinivasan, Executive Director, Population Foundation of India and ex-Director of International Institute of Population Studies
- (9) Prof. S. Tendulkar, Delhi School of Economics and Vice-Chairman, National Advisory Board on Statistics
- (10) Dr. A. B. L. Srivastava, Chief Consultant, Educational Consultants India Ltd., & ex-Professor, NCERT
- (11) Dr. Freddie Ardesir Mehta, Eminent private sector economist and Director, M/s Tata Sons Ltd.

2. The terms *of* reference of the National Statistical Commission are as follows:

- (i) To examine critically the deficiencies of the present statistical system in terms of timeliness, reliability and adequacy.
- (ii) To recommend measures to correct the deficiencies and revamp the statistical system to generate timely and reliable statistics for the purpose of policy and planning in Government at different levels of administrative structure.
- (iii) To recommend permanent and effective coordinating mechanism for ensuring integrated development of the decentralised statistical system in the country;

- (iv) To review the existing legislation for the collection of statistical information and to recommend amendments, where necessary, to achieve the objective of collection and dissemination of timely, reliable and adequate statistics;
- (v) To review the existing organisation of the Ministry of Statistics & Programme Implementation (Statistics Wing) and other statistical units of the Government and to make recommendations on their staffing and training requirements to enable them to cope with the increase and development of statistical services;
- (vi) To examine the need for instituting statistical audit of the range of services provided by the Government and local bodies and make suitable recommendations thereof; and
- (vii) To recommend any other measures for improving the statistical system in the country.

3. The Commission will be assisted by a Secretariat headed by a full-time Secretary at the level of Additional Secretary. Appropriate boarding/lodging, TA/DA and transport arrangements will be made by the Ministry of Statistics & Programme Implementation and regulated as per the instructions issued by the Ministry of Finance from time to time. The Ministry of Statistics & Programme Implementation will meet the expenditure involved in all the activities from the budget allocations of the Ministry.

4. The Commission is expected to submit its report to the Government within a period of twelve months from the date of its establishment.

N.S. SASTRY, Director General and Chief Executive Officer
National Sample Survey Organisation